विषय सूची | पृष्ठ क्रमांक

1. प्रस्तावित विषय का शीर्षक 01
2. प्रस्तावना 01
3. पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा 03
4. अध्ययन के उद्देश्य 16
5. प्रस्तावित विषय पर योगदान 16
6. प्रस्तावित शोध प्रविधि 17
    - अध्ययन क्षेत्र
    - ऑकड़ो का संकलन
    - ऑकड़ों का विश्लेषण
    - शोध परिकल्पना
    - अध्ययन अवधि
    - शोध प्ररचना
7. प्रस्तावित विषय पर आशातीत परिणाम 19
8. अध्ययन की रूपरेखा 19
9. संदर्भ ग्रंथ सूची 20

1 :– प्रस्तावित विषय का शीर्षक

दुर्ग जिले के ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका (पाटन विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

2 :– प्रस्तावना

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । हमारे देश में आज भी 69 प्रतिशत निवासी पर व्यवसाय कृषि पर आधारित है । इस कारण ग्रामीण लोग छः महीने कृषि कार्य करने के बाद बेरोजगार हो जाते है । अतः सरकार का सबसे बड़ा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं ग्रामीण क्षेंत्रों मे ही चलाई जाये ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सकें । केन्द्र सरकार ने पंचायतों को ढेर सारे अधिकार दे दिये है और उन्हें गांव में विकास का उत्तर दायित्व सौंप दिया है । इस तरह पंचायतों का कार्यक्षेत्र बड़ा हो गया है । गांवों में आज सड़क बिजली,पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है, तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से चल रहा है । दुर्ग जिले के ग्राम पंचायते आज ग्राम के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे मनरेगा । इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार गांव में ही प्राप्त हो जाता है । जिससे लोगों को जीवन यापन के लिए गांव छोड़ कर शहर जाना नहीं पड़ता है । इस तरह गांव से शहरी की ओर पलायन पर रोक लगी है और साथ ही ग्रामीण लोगों के आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है ।

महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से ग्रामीण महिलाएँ घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, महिला प्रतिनिधि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है । यद्यपि महिलाओं के लिए नया क्षेत्र है तथा सामंती मनोवृति से जकड़े पुरूष प्रधान समाज में उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है । परंतु उनका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी आने आप को ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक, कम समय में सिद्ध कर दिया । अब विवश होकर राजनैतिक दलो को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देने पड़ रहे है । इस प्रकार महिलाएँ ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही है ।

दुर्ग जिले के ग्राम पंचायते गांव में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हे । शहर के नजदीक या शहर से जुड़े हुए गांव में तो विकास अपनी चरम सीमा पर है और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है लेकिन शहर से दूर – दराज के गांव का विकास आज भी अधूरा है'' जैसे कई ऐसे गांव है जहाँ कच्ची सड़क है, परिवहन सुविधा नहीं है, गांव में पर्याप्त हैण्डपम्प नहीं है, स्कूल के लिए पर्याप्त भवन नहीं है, कई स्कूल भवन जर्जर हालत में है, स्कूल में पीने के लिए हैण्डपम्प नहीं है तथा शौंचालय की भी व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार कई ऐसे समस्याएँ है जिसे पंचायत प्रतिनिधि दूर करने मे असफल रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दूर – दराज के गांवों में परिवहन सुविधाओं का अभाव होता है इसके साथ ही ग्रामीण लोग कम पढ़े लिखे होते है इसलिए पंचायत प्रतिनिधि के कार्यो पर ध्यान भी नहीं देते है । और प्रायः यह भी देखा गया है कि प्रतिनिधी कितना जागरूक व कार्य करने के लिए अग्रसर है, उस पर भी विकास निर्भर करता है ।

अतः सरकार को दुर्ग जिले के इन दूर – दराज के गांवों के विकास पर ध्यान देना चाहिए । ज्यादा से ज्यादा योजनाएँ इन्हीं गांवों में चलाई जानी चाहिए । साथ ही उस गांव के लोगों को भी पंचायत प्रतिनिधि के कार्यो पर ध्यान देना चाहिए एवं प्रतिनिधि चुनते समय हमेशा शिक्षित व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए कयोंकि एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी कार्य कुशल तरीके से कर सकता है, कम पढ़े लिखे की तुलना में । इस प्रकार वह पंचायत निष्चित रूप से पिछड़ेपन से दूर होगी जिस पंचायत की संरपच (प्रतिनिधि) स्वयं पढ़ा लिखा हो, क्योंकि शिक्षा ही नई सोच व दिशा प्रदान करती है । अतः कहां जा सकता है कि ग्रामीण विकास की दिषा में की गई पहल से आज गांव लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है । आज गांव नगरीकरण संस्कृति से परिपूर्ण होते जा रहे है गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही है ।

दुर्ग जिले के ग्राम पंचायते ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है गांव में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य,पेयजल,बिजली, और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं दे रही साथ ही शासन में ग्रामीण लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनमें चेतना और जागरूकता का संचार भी कर रही है । इस प्रकार ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका को नकारा नहीं सकता है ।

3 :– पूर्व शोध साहित्यो की समीक्षा

किसी भी शोध अध्ययन को प्रारंभ करने के पूर्व उस शोध विषय से संबंधित साहित्यो का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है । क्योंकि इससे विषय के बारे में समझने मे मदद मिलती है साथ ही उस विषय पर हुए शोध की जानकारी भी प्राप्त होती है जो कि शोध अध्ययन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है प्रस्तुत शोध अध्ययन, के विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों का विवरण निम्नलिखित है ।

1 डाँ. राजेष, (2005)

डॉ. राजेष के अनुसार ग्राम विकास में पंचायतों का योगदान महत्वपूर्ण होता है । ग्रामीण विकास मुख्यतः तीन मुद्दों से जुड़ा है – पहला ग्रामीण क्षेत्र मं व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करना दूसरा गांवों में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल,बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना एवं तीसरा देष के शासन में ग्रामीण की भागीदारी को सुनिष्चित करने के लिए उनमे चेतना और जागरूकता का संचार करना । अतः इन्ही तीन मुद्दे को लेकर अगर पंचायत कार्य करती है तो वह दिन दूर नहीं जब गांवों में भी शहरो की तरह ही विकास ही विकास दिखाई देगें एवं गांव और शहर में काई अंतर दिखाई नहीं देगा । इस तरह गांवों में भी शहरों जैसी सुविधा मिल सकेगी ।

2 सिंह विमल कुमार (2005)

इन्होंने अपने लेख ग्राम विकास और अप्रवासी भारतीय मे बताया कि बेहतर भविष्य की तलाश में अपने मूलस्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान मे जाकर बसना मानव इतिहास मे एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है । इस प्रकार प्रतिभा पलायन की दो स्वरूप है – पहला गांवों से छोटे – बड़े शहरों की ओर और दूसरा भारत के शहरों से विदेशी शहरों की ओर । भारत मे विदेशों में हो रही प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा होती रही है लेकिन गांवों से शहरों की ओर पलायन को लेकर कम ही चर्चा होती है । ग्रामीण प्रतिभाओं को गांवो में ही उपयुक्त रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया है । यदि किसी ग्रामीण युवा में ऐसी कोई प्रतिभा है तो उसे अवश्य शहर में आकर बसना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है । किंतु अपने प्रतिभा का प्रयोग गांवो के लिए । कर पाना निश्चित रूप से निंदनीय है । इन अप्रवासी भारतीयों का यह नैतिक दायित्व है कि ग्रामीण जनता व ग्राम के विकास के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए जिससे गांवों में चहुमुखी विकास होगा । साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वह इन अप्रवासी ग्रामीणों को ग्राम विकास से जोड़ने का प्रयास करें ।

---

1. **डॉ. राजेष, 2005** :– कुरूक्षेत्र , पत्रिका पृष्ठ क्रमांक 15 से 17,
2. **सिह विमल कुमार 2005 :–** भारतीय पक्ष 2009 पेज नं. 1

3 सिंह, डॉं श्रीमति उषा (2006)

इन्होंने अपने त्रैमाषिक आने शोध अध्ययन मं बताया कि ग्राम पंचायतो को ग्राम के विकास के लिए कोई नई योजनाएँ बनाने की जरूरत नहीं, पहले से चल रही विकास योजनाएँ ग्राम विकास के लिए काफी है । ग्राम पंचायत को पहले से ही चल रह योजनाओं प्रशासनिक सुदृढ़ता के साथ चलाए जाने की आवश्यकता है एवं ग्राम की अंधोसंरचना के विकास योजनाओं पर बल दिया है जिससे गांवो के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके और लोगों को योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकें ।

4 शर्मा स्वाति (2008)

इन्होंने अपने लेख'' भारत में ग्रामीण विकास – चिंता अब भी दूर नहीं में बताया कि भारत गांवो मे रहता है और इसके विकास की अनिवार्य और प्रारंभिक शर्त है – गांवो का विकास । योजना आयोग के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाऍ बनाई गई तथा सभी से ग्रामीण विकास पर निरंतर ध्यान दिया गया । जिसके परिणामस्वरूप लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार हुआ एवं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है । इतना सब होने के बावजूद समस्या का अपेक्षित समाधान खोज पाने मे सरकारी प्रयास सर्वथा अपर्याप्त ही सिद्ध हुए है ।

सरकार द्वारा दी गई निःशुल्क व छुट सहित सहायता से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जीवन स्तर सुधारा भी है । लेकिन एक हकीकत यह भी है कि आज भी 40% गांवो में उचित सड़क नहीं है, 1.8 लाख गांवो में अभी भी एक से दो किसी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं है । लगभग 4.5 लाख गांवो मे अभी भी पेयजल की समस्या है । इसके अलावा लगभग 140 लाख आवसीय इकाईयो की कमी है और स्वास्थ्य सेवाऍ अनेक कमियों से ग्रस्त है । ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का न होना आज भी चिंता का विषय बना हुआ है । आशा की जा सकती है कि अगली पंचवर्षीय योजना इस चिंता को समूल नष्ट करने में सफल हो सकेगी और गांवों के विकास में सहयोग देगी ।

---

3. सिह, डॉ. उषा 2006 :– त्रैमासिक शोध पत्रिका पृष्ठ 9 से 12
4. शर्मा स्वाति 2008 :– humsamvet article 2008 Page No. 1

5 सिंह, डॉ रमन (2009)

तेजी से साकार हो रहा है पंचायती राज का सपना'' यह मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने बिलासपुर में नवनिर्मित जिला पंचायत भवन के लोकार्पण समारोह में कहां । उन्होंने कहां कि छत्तीसगढ़ से आम जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप पंचायती राज का सपना तेजी से साकार हो राह है । गांवो में सड़कों,स्कूल भवनो,ऑगनबाड़ी भवनो और उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाआं के निर्माण विकास और विस्तार में त्रि–स्तरीय पंचायतो ने उल्लेखनीय कार्य किया है । राज्य ने सामाजिक आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है ।

उन्होंने यह भी कहा कि गांव, गरीब और किसानों को बेहतरी के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गयी योजनाआं को जरूरत मंद लोगों तक पहुचाने की बड़ी जिम्मेदारी पंचायतो पर है । प्रदेश की पंचायत अपनी इस जिम्मेदारी को बखुबी निभा रही है । ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश के जिले व पंचायते अपना योगदान दे रही है एवं अघोसंरचना के विकास में उल्लेखनीय कार्य कर रही है ।

6कुमार, लोकेश (2009)

इनके लेख'' गांवो को विकास की ओर ले जाती पंचायते'' से पता चलता है कि आज सामान्यतः पंचायतो के लिए जो कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए उनमें आर्थिक विकास एवं न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि सुधार,लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा व्यवस्था महिला व बाल विकास आदि शामिल है । किंतु पंचायत की भूमिका को और अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि पंचायत में चुने हुए नुमाइन्दे ही नहीं अपितु गांव की प्रत्येक व्यक्ति विकास को अपना कर्तत्य एवं दायित्व समझे और गांव किसी भी मायने में शहर से कम न हो ।

उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों के जरिए गांवो के हालात बदलने का सपना महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने भी देखा था और अब राहुल गांधी भी देख रहे है । केन्द्र सरकार ने गांवों की दशा सुधारने के लिए भारत निर्माण' के नाम से एक विशाल योजना शुरू की और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की दृष्टि से पंचायते को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप विकास की धारा गांवो मं प्रवाहित होना आरम्भ हो गयी है ।

5. सिंह डॉ. रमन 2009 :– रोजगार एवं नियोजन नवंबर 2009 पृष्ठ क्रंमाक 2
6. कुमार लोकेश 2009 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त 2009 पृष्ठ क्रमांक 1 से 7

7 पटेल, डॉं सुधीश कुमार (2009)

इन्होंने अपने ''लेख'' पंचायती राज में रोजगार की बदलती तस्वीर में बताया कि ''ग्राम'' पंचायतो के सामने सबसे जटिल समस्या ग्रामीणों का पलायन रोकने की है । इसके लिए गांव में ही ग्रमवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है । परस्पर सहयोग के आधार पर काम करने से असम्भव कार्य भी संभव हो जाते है । इसलिए लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करवाना पंचायतो का कर्तव्य है । यदि लोगों में कार्य के प्रति रूचि एवं मेहनत करने की आदत बन गई तो पंचायतो के प्रयास भी सफल होंगे और लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अतः ग्रामीण रोजगार प्रबंधंन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी वरन् ग्रामीण विकास भी संभव हो सकेगा । आज जरूरत इस बात की भी है कि हर हाथ को काम मिले और हर काम का उचित दाम मिले, जिससे स्वस्थ एवं सुखमय समाज की रचना होगी और गांवों में सम्पन्नता आएगी ।

8 जोशी, भैया जी (2009)

''इनके लेख ''ग्रामीण विकास की संकल्पना आत्मनिर्भर हो गांव हमारे पता चलता है कि भारत में जब औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ तो देश का सारा तंत्र भी उसी अनुरूप ढलता गया । इस कारण विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण उद्योग – धंधो की अनदेखी हुई । विकास की परिकल्पना में अगर ग्रामीण उद्योग को ध्यान में रखकर रचना की जाती तो शायद देश के विकास की तस्वीर कुछ अलग प्रकार की होती । लेकिन बड़े उद्योगों और केन्द्रित अर्थव्यवस्था के चलते ग्राम उपेक्षित होते चले गये । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम लगातार पिछड़ते चले गये और ग्रामीण रोजगार चौपट होते गये । इसी के साथ कृषि की भी ओर उपेक्षा की गई । जब बड़ी मात्रा में गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर दौड़ने लगे तो वहा भी अनियोजित तरीके से बढ़ती भीड़ के कारण शहरों का संतुलन बिगड़ गया । खेती किसान के लिए एक बोझ व मजबूरी बनती चली गई । उद्योग के क्षेत्र में जिस प्रकार की विकास योजनाएँ बनाई जाती है वैसी कुछ योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं की गई । वैसे हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई सरकारी योजनाएॅ शुरू की गई लेकिन पर्याप्त धन की कमी और क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण उनका कोई लाभ गांवो को नहीं मिल सका । उपर–उपर तो ग्रामीण विकास की योजनाएं बनती रही, उनकी चर्चा होती रही लेकिन जमीनी स्तर पर गांवो का विकास ही मुख्यधारा से कटे रहे । इन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास की सकंल्पना को साकार गुजरात के राजपीपला के पास साकवा गांव कर ही है । गांव के ग्रामीणों के प्रयास से एक ऐसा विकास क्रम निर्माण हुआ है जो सब के लिए प्रेरक हो सकता है कि वहॉ नमक के अलावा कोई चीज शहर से नहीं मंगाई जाती है । इतनी आत्मनिर्भरता वहॉ के ग्रामीणों के अपने गांव में उपलब्ध कराई है । वास्तव में यही ग्रामीण विकास की संकल्पना है ।

7. पटेल डॉ. सुधीश कुमार 2009 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त 2009 पृष्ठ क्रमांक 8 से 12
8. जोशी, भैया जी 2009 :– राष्ट्रीय स्वयं संघ Panchjanya 2009 Page No. 1

9 चौहान, सुरेन्द्र सिंह (2009)

इनके लेख से '' ऐसे होगा गांव का संमग्र विकास'' से पता चलता है कि वास्तव में गांव एक सम्पूर्ण इकाई है । यदि हमारे गांव सुदृढ़ रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी । इस विचार को आधार मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्राम को आदर्श ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है । स्वतंत्रता के पूर्व भी ग्राम विकास की दृष्टि से हमारे महापुरूषों संतो और समाज सेवियों ने निरंतर प्रयास किए है ।

वस्तुतः केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित शासकीय योजनाओं में गांव के आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है । इस प्रकार का विकास अपूर्ण होता है । वास्तव में किसी भी व्यक्ति इकाई या ग्राम के सम्पूर्ण विकास के लिए उसे संस्कार क्षम, नैतिकतापूर्ण शैक्षिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वालम्बी, सदाचारी स्वाभिमानी, परम्पर पूरक तथा प्रमाणिक जीवन के प्रति रूचि जाग्रत करनी होगी । समग्र विकास हेतु गांव के परिसर और उस परिसर में रहने वाले सभी निवासियों के सर्वागीण विकास व संरक्षण करना होगा । इस विचार को ध्यान में रखकर हमने समग्र ग्राम विकास की एक सकंल्पना प्रस्तुत की है ।

10 उपाध्याय, देवेन्द्र (2010)

इन्होंने अपने लेख'' पंचायत राज और महिला संस्कृतिकरण'' (महात्मा गांधी के सपनो का भारत) में बताया है कि भारत सरकार ने संविधान की 73 वां संसोधन विधेयक पारित कर ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतो के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की लागू कर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देकर गांधी जी के सपनो को साकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया । गांधी जी ने ''मेरे सपनो का भारत में पंचायत राज के बारे में जो विचार व्यक्त किये है वे आज वास्तविकता के धरातल पर साकार हो चुके है । क्योंकि देश में समान त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसमें एक एक गांव को अपने पैर पर खड़े होने का अवसर मिल रहा है । और गांव विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है ।

9. चौहान, सुरेन्द्र सिंह 2009 :— कुरूक्षत्र पत्रिका पृष्ठ क्रमांक 40 से 45
10. उपाध्याय देवेन्द्र 2010 :— लोक पंचायत 2010 पेज 1

11 यादव, डॉं हनुमंत (2010)

इन्होंने अपने लेख '' दक्षिण कोरिया में ग्राम विकास'' में कहां है कि एशिया के संदर्भ में जब भी कृषि अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो वह चावल अर्थशास्त्र पर केन्द्रित हो जाती है । इन्होंने बताया कि कृषि एवं ग्राम विकास एक दूसरे से जुडे है तथा एक–दूसरे के पूरक है । ग्राम–विकास का मतलब गांवों में बुनियादी सुविधाएँ ही उपलब्ध करवाना नहीं होता बल्कि शिक्षित स्वस्थ श्रम शक्ति निर्मित करना होता है । दक्षिण कोरिया में ग्रामीण क्षेत्र का मानव विकसा सूचकांक 800 से अधिक है । एशियाई अर्थशास्त्रियों के अभी तक 6 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके है । सभी सम्मेलनो में कृषि एवं ग्राम विकास से जुडे बिंदु तथा कृषि व्यापार के उदारीकरण से संभावित प्रभाव पर चर्चा की जाती रही है ।

12 पाण्डे हरिराम (2010)

इन्होंने अपने लेख '' भारत का विचार और ग्राम विकास'' में यह बात बताई कि 40 के दशक के प्रतिष्ठित दार्शनिक बट्रेंड रसल ने सत्ता की व्याख्या करते हु कहां था कि स्वयं तानाशाही और कम्यूनिज के विरोधी है । पर गांवो के विकास के लिए कम्पयूनिज्म और सोशलिज्म का तरीका ही सरल है ।

लेकिन गांधी जी ने उसी अवधि में ग्राम विकास के न्यूविलयर डिजाइन और समर्थन किया । महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई के दौरान भारत का विचार फला–फूल और विकसित हुआ । यह विचार आजाद भारत का विचार था । जो कुटीर उद्योग और ग्राम विकास के आधार पर आर्थिक प्रगति के लिए एक सुरक्षित सहिष्णु और समतावादी घर होता । लेकिन आजादी के बाद हालत और विचार दोनों बदल गए, विकास के लिए आकार का महत्व बढ़ने लगा और अग्रेंजो द्वारा तैयार किये गये चार मेट्रो शहर की विकास के मानक बनने लगे । देश का काफी हिस्सा पिछड़ने लगे । हमारे नेता और अर्थशास्त्री यह नहीं देख पाये कि हमारी आबादी का तीन चौथाई हिस्सा गांवो व झोपड़ियों में रहता है । भारत तब तक कमजोर रहेगा`जब तक उसकी ताकत चार परम्परागत महानगरो तक ही सीमित रहेगी । इस तरह भारत का विकास तो तभी होगा जब गांव व झोपड़ी में निवासरत रहने वाले लोगों का विकास होगा ।

---

11. यादव डॉं. हुनमंत 2010 – देशबंधु आर्टिकल पेज नं. 1
12. पाण्डेय हरि राम 2010 :– खोज खबर पेज नं. 1

13 कौशिक, डॉ. जगबीर (2010)

इन्होने अपने अध्ययन में बताया कि किसी देश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक उसके गांवो का विकास सम्भव न हो जाए । अतः गांवो के विकास पंचायतो पर ही निर्भर है । अतीत बताता है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास मुख्य धारा से कटा रहा तब तक भारत की नींव विकास के नाम पर खोखली रही है । सरकार द्वारा चलाएद्ध जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं भारत निर्माण योजना के द्वारा पंचायतो गांवो को विकास के मुख्य धारा में जोड़ती है जिसमें गांवो में रहने वाले लोगों एवं गांवों का विकास होता है ।

14 त्रिपाठी रामदत्त (2010)

इन्होने अपने लेख''पंचायतो में पैसा है, पर कर्मचारी नहीं,, में बताया कि विक्रेन्द्रीकरण की नीति के तहत अरबो रूपये ग्राम पंचायतो में जा रहे है लेकिन पंचायतो स्तर पर कोई कार्यालय या पर्याप्त जिम्मेदार स्टाफ न होने से रोजगार ग्राम विकास शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की योजनाएॅ सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है । योजनाओं को तैयार करके उन्हे लागू करने की जिम्मेदारी निर्वाचित ग्राम प्रधान पर डाल दी जाती है जबकि लगभग 3 चौथाई प्रधान सरकारी लिखा पढ़ी और हिसाब किताब करने में सक्षम नहीं माने जाते है । क्योंकि आज भी पंचायतो में कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग प्रतिनिधि होते है ।

यह भी शिकायते है कि समुचित प्रशासनिक मशीनरी के अभाव में पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान बड़े पैमाने पर फर्जी काम या मजदूरी दिखाकर योजनाओं का प्राप्त राशि हडप लेते है । ग्राम प्रधान को भी अपना व अपने परिवार का भी तो पालन पोषण करना है, उनके लिए भी उचित वेतन की वयवस्था होना चाहिए ताकि वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और ईमानदारी से अपना कार्य सकें ।

---

13. कौशिक जगबीर 2010 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका पृष्ठ क्रमांक 23 से 28
14. त्रिपाठी राम दत्त 2010 :– Article BBC News Hindi page no. 1

15 शुक्ला, आसुतोष (2011)

इन्होने अपने अध्ययन में बताया कि भारत की अधिकांश जनता गांवो में रही है अतः ये गांव ही हमे महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है । इतिहास गवाह है कि गांवो पर आधारित कृषक अर्थव्यवस्था वाले देश ही आज विकसित देश कहलात है । अगर हम फ्रांस की बात करे तो यूरोप में सबसे बड़ा कृषक समाज फ्रांस का ही है और इसी कृषक समाज के दम पर फ्रांस आज विकसित देश कहलाता है । भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी प्रमुख तौर से निभाई है और गांवो मं विशेष कार्यक्रमों को लागू किये है ताकि गांवो का विकास हो और देश में मांग आपूर्ति में कमी नहीं सरकार ने हमारे सभी संकट को समाप्त करने के लिए और गांवो की समुचित भूमिका के निर्वहन के लिए हरितक्रांति लाई जिससे देश में अन्न संकट का समापन हुआ गांवो के विकास आम आदमी के हितो को हध्यान में रखकर भ्रष्टाचार मुफ्त बेहतर सब्सिडी पहुच की नीति सरकार ने अख्तियार की है । अप्रैल 2010 से पोषण आधारित सब्सिडी योजना का आरंभ किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 1999 में स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की थी ताकि गरीबी रेखा से नीचे गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजगार उन्मुख कार्यो द्वारा आय की प्राप्ति हो सकें ।

इसी के साथ गांवो में नई पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ भी सुचारू रूप से कार्य कर ही है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ और आजीवका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे है ।

भारतीय संविधान में गांवो पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न संविधान संसाधनो द्वारा ग्राम पंचायतो और जिला पंचायतो को मजबूत बनाया गया है, महिलाओं को भी को मजबूत को भी विशेष तवज्जो लोक तांत्रिक संस्था होने के नाते पंचायतो पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है ।

---

15. शुक्ला अशुतोष 2011 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर 2011 पृष्ठ 39 से 42

16 सिंह, सुरेन्द्र बहादुर (2011)

इन्होने अपने लेख '' पंचायतती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन'' में बताया कि 73 वे संविधान संशोधन के बाद पंचायतो को ढेर सारे अधिकार मिले । इसके बाद पंचायते लगातार सशक्त हो रही है । आज स्थिति यह है कि ग्राम पंचायते आधुनिक सुवधिाओं से लैस हो रही है । केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें ई–गर्वनेंस से जोड़ने की कोशिश की ाज रही है । आज ग्राम–पंचायत स्तर के चुनाव को काफी गंभीरता से लिया गया जाता है । तमाम राजनीतिक दल ग्राम पंचायत चुनाव की स्थिति पर ही देश की जनता की मनोस्थिति का आकलन करते है और उसी आधार पर ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जाती है । पंचायतो को मिले अधिकारो के बाद जिस तरह से बदलाव हो रहा है वह भारत के भविष्य की काफी खुशनुमा तस्वीर दर्शाता है । यही वजह है कि केन्द्र सरकार की ओर से पंचायतो को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है । एक तरफ जहां मिड डे योजना मनरेगा कार्यक्रम लागू करके पंचायतो को ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में सबसे बड़ा हथियार थमाया है वहीं अब खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए गांवो की गरीबी दूर करने के साथ ही पंचायतो को पहले की अपेक्षा कहीं और अधिक सशक्त बनाने की कोशिश है । शिक्षा, पेयजल, जल निकासी, स्वास्थ्य, आवास विकास एवं कानून व्यवस्था में पहले से ही ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है । इस तरह देखा जाए तो केन्द्र से लेकर राज्य स्तर तक की कोई भी योजना शुरू होती है, उसमें गांव की भागीदारी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है । यानी ग्राम पंचायत की भागीदारी के बिना किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं किये जा सकता ।

जगन्नाथ, रतन (2012)

इनके लेख'' ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन'' से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड निरंतर अनुसंधान कर रहे है । इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंक भी अपना योगदान दे रहे है । ग्रामीण और वित्तीय सुविधा विहिन इलाको में वित्तीय साक्षरता और हमारी सक्रिय कार्य प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समृद्धि के लिए सफलता प्राप्त की जायेगी ।वित्तीय समोवशन एवं ग्रामीण विकास के पहलुओं पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि आगामी दिनों में वित्तीय समावेशन की कार्यप्रणाली अधिक गतिमान एवं समस्या रहित होगी, जिससे ग्रामीण इलाको के विकास और योजनाएँ सक्रिय रूप से कार्यान्वित होगी और डॉ. अब्दुल कलाम का नवनिर्मार्ण का सपना वास्तव में बदल जायेगा । सभी ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में अनाज की आपूर्ति होगी, मजदूरो को रोजगार मिले और वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा होगा ।

16. सिंह सुरेन्द्र बहादुर 2011 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त 2011 पृष्ठ 3 से 8
17. जगन्नाथ रतन 2012 :– लोक पंचायत आर्टिक्ल 2012 पेज नं. 1

17 आर,सिंह (2013)

इन्होने अपने लेख'' समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण विकास पर प्रभाव में बताया कि जालौन जिले में ग्रामीण विकास हेतु संचालित समन्वित ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप रोजगार के अतिरिक्त अवसरो का सृजन हो रहा है । जिससे ग्रामीण गरीबों को न केवल गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता मिल रही है अपितु इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों के आय स्तर में भी व्यापक वृद्धि हो रही है। आय स्तर सुधार के कारण उनके रहन–सहन के स्तर खान–पान आदि में भी परिवर्तन की प्रवृति दृष्टिगोचर हो रही है साथ ही उपभोग स्तर में भी वृद्धि होने के कारण उनके आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक स्तरों में भी वृद्धि की प्रवृति अध्ययन क्रम से स्पष्ट रूप से पाई गई । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुछ त्रुटियॉ भी पाई गई इस कार्यक्रम की त्रुटियों को दूर करके सरकार इससे जुड़े सरकारी तंत्र बैंक तथा अधिकारीगण चयनित एवं लाभान्वित ग्रामीण गरीबों से सही सांमजस्य स्थापित कर इसे और भी प्रभावी बना सकते है ।

चतुर्वेदी, पंकज (2013)

इनके लेख'' ग्रामीण विकास की छ.ग. तस्वीर से पता चलता है कि अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ, बैंक बिल्डर सभी गांव की ओर दौंड़ रहे है लेकिन 'उजले भारत' के इन दमकते पोस्टरों के पीछे की त्रासदी और दर्द जान बुझकर, जोत के लिए घटती जमीन खेती की अनावरत घाटे का सौदा होना, इत्यादि को छुपाया जा रहा है । विकास एवं गरीबी उन्मूलन हो रहा है । लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं । इसके लिए सरकार और जनता दोनों को ही आपसी सहयोग से कार्य करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफल बनाना चाहिए । मनरेगा का महत्व इस तथ्य पर निहित है कि इसका संचालन उनके स्तरों पर होता है । यह सवेदनशील वर्गो को ऐसे समय रोजगार उपलब्ध कराता है जब उसके दूसरे साधन कम हो गये है या अपर्याप्त हो, जिससे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध होता है । इन्होने बताया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को पश्चात् सभी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया तथा इन सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य विश्व में ग्रामीण गरीबी निवारण करने का रहा है । इतना ही नहीं, पिछले 65 वर्षो में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर करोड़ों रू. व्यय किये गये है, लेकिन इतनी अधिक राशि खर्च करने के बावजूद भी क्षेत्र की अयोग्यता लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला पा रहे है । अतः इन रूकावटो को दूर कर ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण किया जाना चाहिए।

18. आर, सिंह 2013, :– शोध गंगा 2013

19. चतुर्वेदी पंकज 2013 :– Article Analysis new samay live Rural Development 2013 Page No. 1

20 कुमार, राजू (2013)

उन्होने अपने लेख ''ग्रामीण विकास के लिए जागरूक समूह में बताया कि गांवो के विकास के लिए सरकार स्वैच्छिक संस्थाएँ एवं जनसंगठन अलग–अलग तरीके से कार्य कर ही है । ग्रामीण विकास को लेकर भारत सरकार पिछले कुछ सालो से ज्यादा सकिक्रय दिखाई दे रही है । गांवो में योजनाओं एवं संसाधने में भारी बढ़ोत्तरी हुई ह। इसके बावजूद जिस तेजी से ग्रामीण विकास होना चाहिए था उस तेजी से संभव नहीं हो पा रहा है । गांव के अंदर ऐसा कोई सहयोगी समूह या निगरानी तंत्र दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो गांव में आने वाली योजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर सके, लोगों को अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके या सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भाग ले सके । प्रदेश के कई जिले में सक्रिय ग्रामीण समूहों ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

इन्होने यह भी कहां कि सीहोर के कई पंचायतो में बाल सहयोगी समूह सक्रिय है जो बाल स्वच्छता पर अपनी भूमिका निभा रही है । ये समूह शालाओं में पेयजल शौचालय व्यवस्था व्यक्तिगत साफ–सफाई एवं शालाओं के बाहर भी बाल स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय है । इसमें बाल अधिकारों के प्रति सवेदनशील बच्चों की बातों को पंचायत, ग्रामसभा और सेवादाताओं के समक्ष रखने में सक्षम होने के साथ–साथ समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करने वाले युवा शामिल है । ऐसे समूहो को ग्रामीण विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं के प्रति सक्रिय होना चाहिए ।

निश्चय ही जब ग्रामीण विकास पर सरकारे इतना व्यय कर रही है तो स्थानीय सहयोगी समूह को ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है । ऐसे समूह सभी गांव में बन जाएँ तो बेहतर तरीके से सामाजिक व ग्रामीण विकास हो सकता है ।

---

20. कुमार राजू 2013 :– इंडिया वाटर पोर्टल (हिन्दी), 2013 पेज नं. 1

21 कोट, लोकेन्द्र सिंह (2013)

इनके लेख'' ग्रामीण विकास में महिला जन प्रतिनिधियों की भागीदारी के अध्ययन पता चलाता है कि भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास की एक प्रक्रिया या व्यूहरचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जीवन के ताना–बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है । संविधान के व्यवस्था के साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया । संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था । ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ वर्षो पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है । तथा पंचायतो में उनका प्रतिनिधित्व नही ंके बराबर रहा है । आज ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएॅ निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । आज भले ही पंचायते में महिलाये की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है परंतु यह धारणा बिल्कूल गलत है कि महिलाएं कोई जिम्मेदारी उठाने का तैयार नहीं या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वास्तविकता तो यह है कि महिलाएॅ पुरूषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील बेहतर प्रशासक और उत्तरदायित्व निभाने मे आगे है और जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है उन्होने इस पूरा – पूरा लाभ उठाया है । आज महिला जनप्रतिनिधि के नेतृत्व से भारत के गांव विकास की ओर अग्रसर हो गये है ।

---

21. कोट, लोकेन्द्र सिंह 2013 :– Article Media for rights 2013 Page No.1

22 सिन्हा, विकास कुमार (2013)

इनके लेख'' पंचायतो से सुधर रही है गांवों में जिंदगी से पता चलता है कि पंचायतो की रूपरेखा व कल्पना सदियो पुरानी है । पुरातनकाल से चली आ रही पंचायते देश आजाद होने के बाद और सशक्त हुई । इसमें सच्चाई है कि पुरातनकाल से ज्यादा महिलाओं को पंचायतो में अधिकार मिले है । पंचायतो के सशक्त होने से देश के गांवों में जीवन स्तर में सुधार दिया रहा है । देश की कई पंचायतो को आदर्श पंचायत' का दर्जा प्राप्त है । यह ऑकड़ा जीवन स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है । आज देश के कई गांवो में स्वच्छ पेयजल स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा की सुविधाएँ लोगों को आसानी से मिल रही है । झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तो पंचायतो ने जीवन–स्तर को सुधारने भ्रष्टाचार को रोकने काला बाजारी में अकुंश लगाने में अहम भूमिका निभाई है । कई पंचायते ग्राम–स्तर पर पारदर्शिता की बात कर रही है । यानी ईमानदारी पूर्वक कोशिश होने से गांवों में जीवन – स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है ।

23 श्रीवास्तव, मयंक (2013)

इन्होने अपने लेख''ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर,, में बताया कि भारत गांवों का देश है और इसकी 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः भारत के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास । बिना ग्रामीण विकास के अब्दुल कलाम का 2020 तक भारत के विकसित देश बनने का सपना सिर्फ सपना रह सकता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि,उद्योग,यातयात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हुआ है । पिछले 60 सालो में विकास को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने बड़ी–बड़ी योजनाएँ लागू की है । सरकार की ग्रामीण विकास या निचले तबके की जागरूकता इसी बात से झलकती है कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना का शीर्षक ही समावेशी विकास रख दिया गया और उस गरीबों के लिए कोई एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दसियों कार्यक्रम शुरू किए है जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मार्ग का काम कर रही है । प्रारम्भिक योजनाओं में ही सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनेक रोजगार परक और गरीबी निवारण की विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करने के साथ–साथ वहां मौलिक सुविधाओं के लिए विशेष प्रयास किए जाते है ।

उन्होने यह भी कहां कि ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही विकास की दर को वहां के लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं अथवा अपेक्षाओं के अनुरूप कर पाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हो सके हो लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के जरिए वहॉ के स्कूलों,सड़को, बिजली पानी, मकान जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को काफी मात्रा में गांवों तक पहुचॉने में सफल हो सके ।

22. सिन्हा विकास कुमार 2013 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर 2013 पृष्ठ 37 से 39
23. श्रीवास्तव मयंक 2013 :– कुरूक्षेत्र पत्रिका अक्टूबर 2013 पृष्ठ 7 से 11

4. अध्ययन के उद्देश्य

- ❖ (1) विकास कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीणों के ज्ञान, दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विश्लेषण करना
- ❖ (2) ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्रियांक्ति करने में ग्राम पंचायतो की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना
- ❖ (3) पंचायतो की समस्याओं को जानना एवं सुझाव देना

5. प्रस्तावित विषय पर योगदान

लोकतंत्र की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत यही से प्रारंभ होती है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है । ग्राम विकास में पंचायत की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है । क्योंकि पंचायत ही सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है । सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और भारत निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व तो पंचायतो को ही सौपा जाता है । आज पंचायत के बिना ग्राम विकास का सपना अधूरा हो जायेगा । इसलिए प्रस्तावित विषय का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्ययन से स्पष्ट होगा कि दुर्ग जिले में पंचायते ग्राम विकास में योगदान दे रही है या नहीं अगर नहीं दे रही है तो उसके कौन–कौन से कारण से सकते है इन कारणों को पता लगाना और दूर करने का सुझाव देना ।

6. प्रस्तावित शोध प्रविधि

(1) अध्ययन क्षेत्र

हमने अपने अध्ययन के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के 20 ग्राम पंचायतो को चुना है ।

(2) आंकड़ो का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीय समंको द्वारा आधारित होगा ।

प्राथमिक संमंको के अन्तर्गते न्यादर्श परिवारों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क कर अनुसूची भरकर जानकारियो हासिल की जायेगी । जिला पंचायत दुर्ग से संबंधित आकड़े अध्ययन के लिए एकत्रित किया जायेगा एवं ग्राम पंचायतो के सचिव सरपंच से सम्पर्क ग्राम संबंधित ऑकड़ों का संकलन किया जायेगा ।

द्वितीय संमंको के अन्तर्गत शोध प्रबंधं इंटरनेट, समाचार पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि के द्वारा ऑकड़ो का संकलन किया जायेगा ।

(3) आकड़ो का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध प्रंबंध में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन मापो तकनीको का प्रयोग किया जायेगा । जिनके अन्तर्गत, प्रतिशत विधि औसत विधि गुण संबंध काई वर्ग परीक्षण इत्यादि है ।

(4) शोध परिकल्पना

I साक्षारता में वृद्धि के साथ–साथ बेरोजगारी में कमी आई है ।

II साक्षारता सभी आयु वर्गो में समान है ।

5 अध्ययन अवधि – अध्ययन अवधि 2013 – 2016 तक होगा ।

6 शोध प्ररचना

प्रस्तुत शोध अध्ययन में हमने दुर्ग जिलें के ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका के अध्ययन के लिए पाटन विकासखण्ड 784 परिवारों को न्यादर्श के रूप में चुना जिसमें कि मध्यम वर्ग एवं गरीबों रेखा के नीचे रहने वाले परिवार शामिल है । न्यादर्श परिवारों के चयन हेतु अपनाई गई पद्धति निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट की गई ।

तालिका

क्र	गांव के नाम	परिवारों की संख्या	स्मग्र का प्रतिशत 20 %	न्यादर्श का आकार
1	सांकरा	255	2.55 x 20	51
2	सेलूद	452	4.52 x 20	50
3	धौराभाठा	240	2.40 x 20	48
4	पतोरा	239	2.39 x 20	47
5	परसाही	141	1.41 x 20	28
6	गाढ़ाडीह	138	1.38 x 20	27
7	जामगांव आर	186	1.86 x 20	37
8	जामगांव एम	312	3.12 x 20	62
9	फुंडा	191	1.91 x 20	38
10	छाटा	156	1.56 x 20	31
11	गोडपेंड्री	261	2.61 x 20	52
12	छेवादा	193	1.92 x 20	38
13	मर्रा	213	2.13 x 20	42
14	चुनकट्टा	139	1.39 x 20	28
15	ढौर	170	1.70 x 20	34
16	फेकारी	159	1.59 x 20	32
17	रानीतराई	161	1.61 x 20	32
18	कुम्हली	156	1.56 x 20	31
19	माहकाकला / मुडपार	200	2.00 x 20	40
20	भरर	182	1.82 x 20	36
कुल		4144		784

7. प्रस्तावित विषय पर आयातीत परिणाम

प्रस्तावित विषय पर आशातीत परिणाम यह होगा कि इससे समाज को यह जानकारी मिलेगी कि ग्राम के विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती है तो उनके आर्थिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है ।

इसके अलावा आशातीत परिणाम यह होगा कि लोग जागरूक एवं सजग होंगे कि ग्रम पमुख के कार्य से उनके एवं गांव का विकास हो रहा है या नहीं एवं गांव के लोग सरपंच जैसे प्रतिनिध चुनते समय योग्य कुशल एवं पढ़े लिखे लोगों को ही वरीयता देगें और ग्रम सभा की बैठक में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेगें और अपने विचार ग्राम सभा में रखेंगे जिससे गांव का आर्थिक व सामाजिक विकास हो सकें ।

8. अध्ययन की रूपरेखा

अध्ययन की रूपरेखा के अन्तर्गत हमने अपने अध्ययन को सात भागों में विभक्त किया :–

प्रथम अध्याय में हमने गांव के विकास में ग्राम पंचायत के योगदान में संबंधित प्रस्तावना महत्व अध्ययन के उद्देश्य शोध परिकल्पना,अध्ययन अवधि,अध्ययन के क्षेत्र अध्ययन की सीमाएँ एवं अध्ययन की रूपरेखा है ।

द्वितीय अध्याय में दुर्ग जिले का परिचय है जिसके अन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि जिले का निर्माण भौगोलिक स्थिति और विस्तार,जनसंख्या,साक्षरता दर, नगर एवं पंचायत विकासखंड एवं तहसील लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र, दर्शनीय स्थल, भूसंरचना मिट्टी,नदियां, जलवायु, कृषि, वन, खनिज एवं उद्योग धंधे, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधायें, विद्युतीकरण सुविधायें एवं ग्राम पंचायतो का परिचय है ।

- ❖ तृतीय अध्याय में हमने पूर्व शोध साहित्यों की समीक्षा है ।
- ❖ चतुर्थ अध्याय में न्यादर्ष परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना है । गुण संबंध एवं काई वर्ग परिक्षण किया गया है ।
- ❖ पंचम अध्याय ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन है ।
- ❖ षष्टम अध्याय में ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का मूल्यांकन है ।
- ❖ सप्तम अध्याय में अध्ययन के निष्कर्ष समस्या एवं सुझाव है ।
- ❖ अष्टम अध्याय में संदर्भ ग्रंथ सूची है ।

9. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार विमल 2005 – ग्राम विकास और अप्रवासी भारतीय, भारतीय पक्ष 2005
2. चौहान सुरेन्द्र सिंह 2009 – ऐसे होगा गांव समग्र विकास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आर्टिकल Panchjanya 2009
3. गोविंदाचार्य के.एन. 2009 – केन्द्रीय बजट 7 प्रतिशत गांव को मिले भारतीय पक्ष जुलाई 2009
4. सिंह, डॉ. रमन 2009 – रोजगार एवं नियोजन नवंबर 2009 पृष्ठ क्रमांक 2
5. यादव, शंभूनाथ 2010 – निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका, कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृष्ठ, 3 से 8
6. यादव, अखिलेश चंद्र 2010 – बदलेत गांव, उभरता देश कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृष्ठ क्र. 8 से 18 तक
7. मीना जनक सिंह 2010 – ग्रामीण विकास के विविध आयम पृष्ठ 34 से 53 तक
8. यादव डॉ.हनुमंत 2010 – दक्षिण कोरिया में ग्राम विकास आर्टिकल देशबंधु
9. सिंह मनकित 2011 – एक ज्वलंत मुदा ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण विकास जागरण जक्शन पेज नं. 1
10. मूर्ति अरविंद 2011 – ग्राम सभा बनाम ग्राम पंचायत हिन्दी सिटीजन आर्टिकल फरवरी 2011
11. दत्त, गौरव 2011 – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चंद एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक – 361 से 422 तक
12. मनीषा अक्टूबर 2011 – ग्रामीण विकास में बहुविद्य पहलो का स्वरूप कुरूक्षेत्र पत्रिका पृष्ठ 3 से तक
13. कुमार अवधेश 2012 – संवाद सेतु ग्राम विकास राष्ट्रीय दिल्ली संस्करण पेज
14. सागर आशीष 2012 – केन्द्रीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012–13 बुंदेलखंड पोर्टल
15. चंदन मुकेश पाण्डेय 2012 – भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम आर्टिकल लक्ष्य 2012
16. कांशी ए.बी 2012 – ग्रामीण विकास कि राह पर तेजी से बढ़ता छत्तीसगढ़ आर्टिकल भास्कर न्यूज अगस्त 2012

17. दुबे डॉ. साचीदानंद 2013 – मनरेगा ग्रामीण विकास Snsamaj news page I 2013
18. कुमार यशवंत 2013 – अपने बूते गांव का विकास आर्टिकल पत्रिका न्यूज मार्च 2013
19. अख्तर कमाल 2013 – ग्राम पंचायत सफल मीलो का दैनिक जागरण सितम्बर 2013
20. कुमार, राकेश अक्टूबर 2013 – ग्रामीण भारत का सुधरता जीवन स्तर कुरूक्षेत्र, पृष्ठ क्रमांक 20 से 23

शोध निर्देशक	सह निर्देशक	शोधछात्रा
डॉ. रक्षा सिंह (प्राचार्य)	डॉ. बी. एल सोनेकर	कु.कल्याणी
श्री शंकराचार्य महा.	व्याख्याता	अर्थशास्त्र अध्ययन
सेक्टर – 6, भिलाई	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला शाला	
	पं.र.शु.वि.वि. रायपुर (छ.ग.)	

विभागाध्यक्ष

प्रो.आर.प्रसाद

अर्थशास्त्र अध्ययन शाला

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

Professor & Head
School of Studies in Economics
Pt. R.S.S. University, Raipur